भारत की अफगाण सबध

डॉ.सागरकुमार विठ्ठल जाधव, सहाय्यक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, कला वाणिज्य महाविद्यालय, कासेगाव

प्रस्तावना :

भारत और अफगानिस्तान के संबंध बेहद मज़बूत और मधुर हैं। अफगानिस्तान जितना अपने तात्कालिक पड़ोसी पाकिस्तान के निकट नहीं है, उससे कहीं अधिक निकटता उसकी भारत के साथ है। भारत अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाता रहता है। अफगानिस्तान के शीर्ष नेता समय-समय पर भारत दौरे पर आते रहते हैं जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी का पता चलता है। लेकिन समय-समय ऐसी गतिविधियाँ भी होती रहती हैं जो दोनों देशों के संबंधों में चुनौती सी प्रतीत होती हैं।भारत अफगान-संचालित और अफगान-स्वामित्व वाली शांति और समाधान प्रक्रिया के लिये अपने सहयोग को बराबर दोहराता रहा है।

भारत-अफगान संबंध

भारत- अफगानिस्तान के आधारभूत ढाँचे के विकास में व्यापक मदद कर रहा है भारत ने जेरांग-देलराम सड़क परियोजना या सलमा बाँध शक्ति परियोजना स्थापित करने में, इंदिरा गाँधी शिशु स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, काबुल में हबीबी स्कूल की स्थापना आदि में महत्त्वपूर्ण सहायता दी है इसके अतिरिक्त भारत-अफगानिस्तान में कृषि, बैंकिंग, कंप्यूटर, खनन, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में सहायता के लिए बार-बार प्रतिबद्धता व्यक्त की है. दरअसल, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में भारत का अहम साथी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक रूप से मज़बूत और दोस्ताना रहे हैं।१९८० के दशक में भारत-अफगान संबंधों को एक नई पहचान मिली, लेकिन 1990 के अफगान-गृहयुद्ध और वहाँ तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद से दोनों देशों के संबंध कमज़ोर होते चले गए। इन संबंधों को एक बार फिर तब मजबूती मिली।जब २००१ में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया और इसके बाद अफगानिस्तान के लिये भारत मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता बन गया है।

२००१ में अमरीका के नेतृत्व में उत्तरी गठबंधन की सेनाओं ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण किया और इस दौरान भारत ने अपनी ख़ुफ़िया सेवाएं दी और अन्य तरह की सहायता मुहैया कराई। अफ़ग़ानिस्तान की सरकार के तालिबान से मुक्त हो जाने के बाद भारत ने दोबारा अफ़ग़ानिस्तान से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये। इसके बाद से ही भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को लगातार मानवतावादी सहायता और आर्थिक मदद दी है।

आंकड़े बताते हैं कि साल २०००-२०१७ के बीच भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को लगभग ४४०० करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद दी है। यह क्षेत्रीय तौर पर सबसे ज़्यादा और अन्तराष्ट्रीय तौर पर ५ वीं सबसे बड़ी मदद है। भारत अफ़ग़ानिस्तान को हवाई रास्ते से जोड़ना, पावर स्टेशन निर्माण, स्वस्थ्य और शिक्षा में निवेश जैसे कार्य कर रहा है।इसके अलावा उसकी सरकारी अधिकारियों, पुलिस और राजनयिकों की ट्रेनिंग में भी मदद कर रहा है।२००९ में भारत के बॉर्डर रोड्स आर्गेनाईजेशन ने एक बड़े सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के अंतर्गत अफ़ग़ानिस्तान के निमरोज़ राज्य में देलाराम से ज़रांज्को जोड़ने वाली सड़क का निर्माणकार्य पूरा किया।

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के कार्यकाल में दोनों के बीच कई और महत्वपूर्ण समझौते हुए जिससे आपसी रिश्तों में काफ़ी गर्मी दिखी।२००६में राष्ट्रपति करज़ई के भारत दौरे में ग्रामीण विकास, शिक्षा और मानकीकरण को लेकर तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उसी वर्ष, भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को दिये जाने वाले राहत पैकेज को १५० मिलियन डॉलर से बढ़ाकार ७५० मिलियन डॉलर कर दिया। २००७ में अफ़ग़ानिस्तान 'सार्क' देशों का ८ वां सदस्य बना।

२०११ में भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को ढाई लाख टन गेहूँ दान में दिया।२०११ में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त सैन्य सहयोग पर भी सहमती बनी जिससे अफ़ग़ान सुरक्षा बलों को भारतीय सैनिकों की तरफ़ से ट्रेनिंग दी जा रही है। २०१५में वर्त्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफ़ग़ानिस्तान का दौरा किया जिस दौरान भारत ने उसे३ एमआई-२५ लड़ाकू हेलिकॉप्टर दान में दिये। २५ दिसंबर २०१५ को ९० मिलियन डॉलर की लागत से बना, भारत द्वारा निर्मित, अफ़ग़ानिस्तान के संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी एवं मौजूदा अफ़ग़ान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उद्घाटन किया।

अफगानिस्तान में भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों से विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग तीन अरब डॉलर की सहायता दी है जिसके तहत वहाँ संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। वहाँ कई मानवीय व विकासशील परियोजनाओं पर भारत अभी भी काम कर रहा है। यही वज़ह है कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में सबसे अधिक लोकप्रिय देश भारत को माना जाता है। इस संदर्भ में दोनों देश अधिक प्रभाव वाली ११६ सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम करने के लिये सहमत हुए हैं जिन्हें अफगानिस्तान के ३१ प्रांतों में क्रियान्वित किया जाएगा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके तहत काबुल के लिये शहतूत बांध और पेयजल परियोजना(सिंचाई में भी सहायक) पर काम शुरू किया जाएगा। अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिये नानगरहर प्रांत में कम लागत पर घरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनके अलावा, बामयान प्रांत में बंदए-अमीर तक सड़क संपर्क, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिये जलापूर्ति नेटवर्क और मजारए-शरीफ में पॉलीटेक्नीक के निर्माण में भी भारत सहयोग दे रहा है। कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ANASTU) की स्थापना के लिये भी भारत ने सहयोग का भरोसा दिलाया है।

भारत से सहायतानुदान के अंतर्गत निम्नलिखित नई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर भी सहमति हुई

१. काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना जो सिंचाई में सहयोग प्रदान करेगी;

२. पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए नानगरहर प्रांत में अफगानिस्तान शरणार्थियो के लौटने के लिए कम लागत पर घरों का निर्माण;

३. बामयान प्रांत में बंदए-अमीर तक सड़क संयोजनता जो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करेगी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी

४. परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति नेटवर्क

५. मूल्यवर्धित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए काबुल में जिप्सम बोर्ड विनिर्माण संयंत्र की स्थापना; और

६. मजार-ए-शरीफ में पॉलीटेक्नीक का निर्माण।

दिसम्बर, 2016 में अमृतसर में ऐतिहासिक हार्ट ऑफ एशिया-इस्ताबुल प्रक्रिया (एचओए) मंत्रालयी सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता का स्मरण करते हुए अफगानिस्तान ने भारत द्वारा व्यापार, वाणिज्य और निवेश के क्षेत्रों में एचओए के आत्मविश्वास निर्माण उपाय के अंतर्गत किए गए उल्लेखनीय कार्य तथा ट्रेड पोर्टल के सॉफ्ट लांच का स्वागत किया। दोनों पक्ष क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के अंतर्गत कार्य करने के लिए सहमत हए। यूएन तथा डब्ल्यूटीओ में पारस्परिक हिते क मामलों पर समन्वय करने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई। मई, 2017 में प्रक्षेपित दक्षिण एशियाई उपग्रह में अफगानिस्तान की भागीदारी से भारत रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में अफगानिस्तान की और अधिक मदद कर रहा है।इससे पता चलता है कि भारत कैसे अफगानिस्तान में मानवीय और विकासशील परियोजनाओं के विकास के लिये प्रतिबद्ध है,लेकिन सुरक्षा के मसलों पर क्या कुछ किया जा सकता है, यह अभी भी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है

भारत और अफगाण के दरम्यान राजनीतिक और सुरक्षा परामर्श

दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में आतंक और हिंसा की घटनाओं पर गंभीर चिंता दर्शाई जिसके परिणामस्वरूप अनेक मासूम लोगों की जानें गईं । यह देखते हुए कि आतंकवाद किसी क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों की शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध आतंकवादियों को सहायता, राष्ट्र तथा प्रायोजन, सुरक्षित स्थानों और उनके अभ्यारण्यों के सभी स्वरूपों को समाप्त करने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति हुई। भारत ने आतंकवाद, संगठित अपराध, स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार और धन-शोधन के संकट के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने पर सहमति दी। भारतीय पक्ष ने एक अफगान-संचालित और अफगान-स्वामित्व वाली शांति और समाधान प्रक्रिया के लिए अपने सहयोग को दोहराया। यह सहमति हुई कि अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सफलता के लिए हिंसा की तत्काल समाप्ति हेतु ठोस, अर्थपूर्ण और सत्यापनीय कदम उठाए जाएंगे।

भारत के अफगाणिस्तान संबंध मेंसमक्ष चुनौतियाँ :

विकास के मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना वहाँ की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अमेरिकी सेना यदि अफगानिस्तान से चली जाती है तो वहाँ तालिबानियों का प्रभुत्व कायम हो जाने की आशंका है। ऐसे में भारत को अपनेद्वारा वित्तपोषित विकास परियोजनाओं चुनौतियाँनिर्माण हो गई है। भारत के अफगाणिस्तान संबंधमें आतंकवाद एक समस्या है। इस समस्या के चलते अफगाणिस्तान में भारत की सहाय्यता करते समय समस्या निर्माण हो रही गईहै।

भारत व अफगाण नीती में भारत के भविष्य के प्रयासा

गौरतलब है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिये अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश में शांति कायम होना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि एक पड़ोसी के रूप में भारत को अफगानिस्तान का साथ मिलता रहे। इसके लिये अफगानिस्तान में विकास कार्यों के अलावा भारत को अफगानिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रश्न अफगानिस्तान की सुरक्षा का है तो भारत को चाहिये कि वह इस मुद्दे पर रूस और चीन से संवाद करने का प्रयास करे। एक अन्य उपाय यह हो सकता है कि यदि भारत चाहे तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भी अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज सकता है, लेकिन इसके लिये संयुक्त राष्ट्र को नेतृत्व की कमान संभालनी होगी।भारत यह भी जानता है कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका को कम करने की नीति पर पाकिस्तान लंबे समय से काम कर रहा है। इसीलिये भारत पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिये सार्क के बजाय BIMSTEC, BBIN और IORA (Indian Ocean Rim Association) जैसे क्षेत्रीय समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिये भारत को इसी तरह कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता बनाए रखनी होगी।

निष्कर्ष :

अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे के पड़ोस में स्थित दो प्रमुख दक्षिणएशिया देश हैं। दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रिय सहयोग संगठन (दक्षेस) के भी सदस्य है। यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अफगानिस्तान में पाकिस्तान का स्थायी एजेंडा वहाँ अपनी सामरिक पहुँच बनाना है, रणनीतिक भागीदारी के रूप में द्विपक्षीय विकास सहयोग को मान्यता प्रदान करते हुए तथा अफगानिस्तान में सामाजिक, आर्थिक, अवसंरचना और मानव संसाधन विकास के लिए भारत द्वारा अफगानिस्तान को प्रदान की गई २ बिलियन यूएस डॉलर की विकास और आर्थिक सहायता के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष एक महत्वाकांक्षी तथा अग्रदर्शी अगली पीढी कीनई विकास भागीदारी' आरंभ करने पर सहमत हुए। उसी प्रकार भारत के स्थायी लक्ष्य भी स्पष्ट हैं- अफगानिस्तान के विकास में लगे करोड़ों डॉलर व्यर्थ न जाने पाएँ, काबुल में मित्र सरकार बनी रहे, ईरान-अफगान सीमा तक निर्बाध पहुँच रहे और वहाँ के पाँचों वाणिज्य दूतावास बराबर काम करते रहें। इस एजेंडे की सुरक्षा के लिये भारत को अपनी कूटनीति में कुछ बदलाव करने भी पड़ें

संदर्भसूची:

1. Foreign affairs Ministry Report -1992 to 1995. Government in India
2. Harsh V. Pant, ‘ India's Afghan Muddle Hardcover’ – 28 August 2014
3. J.N. Dixit and Rahees Singh, Bhartiya Videsh Niti (Indian Foreign Policy) 1 January 2018
4. Drustiias.com